

मास्टर प्लान | सिमरोल रोड पर एकेडमिक जोन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्कूल सहित भवन बनेंगे

800 करोड़ में बनेगा आईआईटी

» बैठक में मंजूर हुआ » लगभग 24 महीने में निर्माण होगा पूरा » एंट्रेंस तक फोरलेन बनाने का प्लान

दूसरी आईआईटी से किसी भी मामले में पीछे नहीं होगा अपना आईआईटी।

संजय गुप्ता | इंदौर

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) इंदौर निर्माण का मास्टर प्लान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की बैठक में मंजूर हो गया है।

आईआईटी फैक्ट

502 एकड़ जमीन सिमरोल में है

2.21 लाख स्क्वियर मीटर का निर्माण होगा

760 करोड़ रुपए के हिसाब से साल 2006 की दरों पर प्रोजेक्ट

388 करोड़ रुपए लगेंगे आधारभूत ढांचे पर

131 करोड़ रुपए उपकरण खरीदी व 241 करोड़ रुपए मैटेनैस पर खर्च होंगे

1500 करोड़ का होगा मास्टर प्लान दर् से संशोधित होगी

सिमरोल में 502 एकड़ जमीन पर बनने वाले आईआईटी के स्थाई भवन के लिए समय सीमा काम शुरू होने के दिन से 24 माह रखी गई है। आईआईटी के आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए साल 2006 की मंजूर दर से 388 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसे संशोधित किया जा रहा है। अब निर्माण की लागत करीब 800 करोड़ अनुमानित की गई है।

दो प्रवेश द्वार रहेंगे- आईआईटी इंदौर में प्रवेश के लिए दो द्वार रहेंगे। दोनों उत्तर-पश्चिम दिशा में होंगे। इस संबंध में आईआईटी यह भी विचार

कर रहा है कि मुख्य मार्ग से अंदर आईआईटी तक आने के लिए करीब 800 मीटर की दूरी पर फोरलेन बनाया जाए।

कुछ इस तरह रहेगा आईआईटी

उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया काल्पनिक मैप

» उत्तर दिशा में- होस्टल रहेंगे

प्रस्तावित फोरलेन रोड

सिमरोल रोड

» उत्तर-पश्चिम दिशा में- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहेगा

» दक्षिण दिशा में- फैक्ट्री व स्टाफ के रहने के लिए भवन व स्कूल रहेगा

हर भवन से दिखेगी हरियाली

उत्तर
पश्चिम
पूर्व
दक्षिण

» उत्तर-पूर्व दिशा में- वनविभाग की जमीन है, इसे निर्माण से मुक्त रखा जाएगा

सुलझा करोड़ों का मुद्दा

हाल ही में हुई बीओजी बैठक में जमीन के लिए केंद्रीय पर्यावरण व वन विभाग को दी जाने वाली 10.70 करोड़ रुपए की राशि का मुद्दा सुलझ गया है। रजिस्ट्रार श्री राजशेखर ने बताया बैठक में शामिल हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव संजय सिंह ने आश्वासन दिया है कि शासन जल्द इस राशि का भुगतान करेगा।

दूसरे चरण की मंजूरी जल्द

502 एकड़ जमीन में से 198 एकड़ वन विभाग की है। इस पर निर्माण के पहले चरण की मंजूरी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय से आ गई है। शासन से 10.70 करोड़ रुपए मिलते ही दूसरे व अंतिम चरण की मंजूरी भी मिल जाएगी।

जून 2013 का है लक्ष्य

हाल ही में लोकसभा में उज्जैन सांसद प्रेमचंद गुड्डु ने आईआईटी निर्माण की समय सीमा पूछी थी। इस पर केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री बी पुरंदेश्वरी ने जून 2013 तक निर्माण होने की बात कही थी। आईआईटी प्रबंधन दूसरे चरण की मंजूरी के बाद निर्माण के लिए 24 माह की समय सीमा लेकर चल रहा है।

मास्टर प्लान में यह ध्यान रखा गया है कि हर ब्लॉक की ऊंचाई इस तरह रखी जाए जिससे उत्तर-पूर्व में वन विभाग की छोड़ी जा रही हरियाली हर ब्लॉक से सभी को दिखे। साथ ही इस जमीन (198 एकड़) के मात्र 25 फीसदी (करीब 50 एकड़) पर ही निर्माण किया जाएगा।